

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

सामाजिक क्षेत्र

- भारत विश्व की सबसे युवा आबादी का घर है, क्योंकि इसकी आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। यूएनएफपीए, 2018 ने यह अनुमान लगाया है कि भारत को यह जनसांख्यिकीय लाभ कितने दशकों तक सुलभ होगा जो कि विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है?

- पांच दशक (वर्ष 2005-06 से 2055-56 तक)

- वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों और अन्य 169 लक्ष्यों के संग्रह को क्या कहा जा रहा है?

- संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG)

- संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG: Sustainable Development Goals) में भारत के प्रदर्शन को मापने के लिए किस संस्था ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसडीजी भारत सूचकांक (SDG India Index) विकसित किया है?

- नीति आयोग

- वर्ष 2018 के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार, केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु शीर्ष तीन स्थानों पर विराजमान हैं। आकांक्षा श्रेणी में सबसे निचले स्थान पर कौन-से तीन राज्य हैं?

- उत्तर प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश

- महिलाओं के वित्तीय समावेशन को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक आवश्यक उपकरण माना जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर बैंक या बचत खाते रखने वाली महिलाओं का अनुपात वर्ष 2005-06 में 15.5% था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर कितना हो गया?

- लगभग 53%

- वर्ष 2019-20 के जेंडर बजट में 30 मंत्रालयों/विभागों ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके यहां महिलाओं के मद में स्कीमें चलाई जा रही हैं जिन पर 1,31,699.52 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। यह राशि कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत है?

- लगभग 5%

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा जीडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर खर्च 1.5% से बढ़कर करीब 7% हो गया। इसके फलस्वरूप सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 में 6.2% से बढ़कर वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में कितना हो गया?

- मात्र 7.7%

- सभी सामाजिक क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जिसके फलस्वरूप जीडीपी का सार्वजनिक व्यय 2014-15 में 2.8% से बढ़कर 2019-20 में कितना हो गया?

- मात्र 3.1%

मिशन इंड्रधनुष

भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंड्रधनुष शुरू किया। इस लक्षित कार्यक्रम के तहत उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। इस अभियान में उन जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जहां बच्चों को किसी न किसी वजह से टीकाकरण का फायदा नहीं मिल सका। मिशन इंड्रधनुष के तहत दो राउंड के दौरान पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि की वार्षिक दर 1% से बढ़कर 6.7% हो गई है। इसके अतिरिक्त नए टीके निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी), वयस्क (एडल्ट) जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, खसरा-रुबेला (एमआर) वैक्सीन, निम्नोकोकल वैक्सीन (पीसीवी) को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत के प्रधानमंत्री ने 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (MODWS) द्वारा आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ थी, जो वर्ष 2014 से पहले देखी गई, की तुलना में काफी तेज गति से घटकर जनवरी 2018 में 25 करोड़ रह गई। अब तक, सम्पूर्ण भारत में 296 जिलों और 307349 गांवों को खुले

जीडीपी के संदर्भ में सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय (प्रतिशत)

सेवाएं/वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ^{RE}	2018-19 ^{BE}
सामाजिक सेवाएं	6.6	6.2	6.6	6.8	6.7	7.6	7.7
शिक्षा	3.1	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.1
स्वास्थ्य	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6
अन्य	2.3	2.1	2.5	2.6	3.0	3.0	3.0

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2019-20; RE: संशोधित अनुमान; BE: बजट अनुमान

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- कुल वजतीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा वर्ष 2013-14 में 24.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में कितना हो गया? - **पात्र 26 प्रतिशत**
- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों की संख्या (60+) सात करोड़ 70 लाख थी और 2011 की जनगणना में बताया गया कि यह संख्या जल्दी ही 10 करोड़ को पार कर जायेगी। पिछले एक दशक में भारत में वयोवृद्ध लोगों की आबादी किस दर से बढ़ी है? - **करीब 39.3 प्रतिशत**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बैंक खाते से कितने लोगों को जोड़ने की योजना है? - **15 करोड़ लोगों (7.5 करोड़ परिवारों)**
- 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत हर खाताधारक को एक डेबिट कार्ड के साथ कितनी राशि का दुर्घटना बीमा कवर दिया जायेगा? - **एक लाख रुपये**
- उक्त योजना के तहत इस खाते के छह महीने तक संतुषजनक परिचालन होने के बाद आधार से जुड़े खातों पर कितनी राशि तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति भी दी जायेगी? - **पांच हजार रुपये**
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी परिवारों के लिए बैंक खातों खोलने वाला पहला राज्य कौन बना? - **केरल**
- 20 जनवरी, 2015 को केंद्र सरकार की किस योजना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनायी है? - **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**
- भारतीय बैंकों ने पांच महीने की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले? - **11.50 करोड़**
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के सबसे सफल कार्यान्वयन लिए भारत के किस प्रमुख सार्वजनिक बैंक को फरवरी 2016 के प्रथम सप्ताह में सर्वोत्तम बैंक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? - **पंजाब नेशनल बैंक**
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना में मासिक पेंशन को कम से कम कितने रुपये करने की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना 28 अगस्त, 2014 को जारी कर दी गई? - **1,000 रुपये**
- कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किए जाने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए 18 सितंबर, 2018 को किस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत बीमित व्यक्तियों को नौकरी जाने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जायेगी? - **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना**
- वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम को अपनाने वाले लोगों के 60 वर्ष के होने पर उन्हें 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। इस स्कीम के लाभार्थी किस क्षेत्र के श्रमिक होंगे? - **असंगठित क्षेत्र**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में **राष्ट्रीय घोषण मिशन** की शुरुआत की, जिसके तहत सभी 36 राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में उच्च कुपोषण भार के क्षेत्रों में कार्यवाई करना लक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य कब तक कुपोषण रहित भारत बनाना है? - **वर्ष 2022 तक**
- केंद्र सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई किस योजना के तहत 15,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले नए कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में 12% का योगदान कर रही है? - **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना**

में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और चंडीगढ़ को पूर्णतः ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।

दिव्यांग सारथी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग सारथी मोबाइल एप के बीटा संस्करण का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को आसानी से जानकारी मिल सकेगी। यह एप्लीकेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान के आईसीटी घटक का एक अभिन्न हिस्सा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारी, जैसे विभिन्न नियमों, दिशानिर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना है।

ई-संवाद

ई-संवाद एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो एनजीओ और सिविल सोसायटीज के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ बातचीत करने के लिए मंच प्रदान करता है। ई-संवाद के माध्यम से एनजीओ और सिविल सोसायटी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, शिकायतें डाल सकते हैं, सर्वोत्तम व्यवहार साझा कर सकते हैं, जो प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करेंगे।

जीआईएन (ज्ञान)

30 नवंबर, 2015 को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्व शैक्षिक नेटवर्क पहल (GIAN: The Global Initiative of Academic Networks) लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का सहयोग लेना है ताकि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी नियुक्ति

वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** की शुरुआत 2007 में की गई। इसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 कर दी गई है। जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उनकी पेंशन राशि 200 रुपये के स्थान पर कितनी कर दी गई है? - 500 रुपये प्रति माह
- केन्द्र सरकार ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए किस कार्यक्रम के तहत वृद्धजन देखभाल केन्द्र 21 राज्यों के 100 जिला अस्पतालों में खोलने की योजना बनायी है? - **राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)**
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। यह केन्द्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई? - 1 अक्टूबर, 2007 को
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 रुपये रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक वर्ष में कितनी राशि तक की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है? - 30 हजार रुपये
- गरीबी रेखा से सम्बद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवनवापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली किस योजना का शुभारम्भ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 1 अप्रैल, 2017 को किया गया? - **राष्ट्रीय बयोश्री योजना**
- पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त राष्ट्रीय बयोश्री योजना का उद्देश्य आयु संबंधी बीमारियों (कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, दांतों का टूट जाना एवं विकलांगता आदि) का सामना कर रहे गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी से सम्बद्ध बुजुर्गों को जीवनवापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सामान्य अथवा सामान्य के करीब लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान किस कोष से मिलेगा? - **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष**
- केंद्र सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बार फिर **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (बीपीबीवाई)** की शुरुआत 14 अगस्त, 2014 को की। यह योजना एक वर्ष के लिए कब से कब तक के लिए शुरू की गई है? - 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 नवंबर, 2014 को पेंशनभोगियों के लिए 'आधार कार्ड' पर आधारित कौन-सा सर्टिफिकेट लांच किया? - **डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट**
- केंद्र सरकार ने 19 जनवरी, 2016 को **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)** के तहत सरकार के सह-अंशदान की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी? - 31 मार्च, 2016 तक
- 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 में **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)** शुरू की। इसकी अवधि कब तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? - मार्च 2020 तक
- 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगी। अगर वार्षिक पेंशनविकल्प चुने तो 10 वर्षों के लिए 8.3% की गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगी। इसके तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? - 15 लाख रुपये
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगों की संख्या 2001 के 2.19 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई? - लगभग 2.68 करोड़

को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे देश के मौजूदा शैक्षिक संसाधनों का प्रसार, गुणवत्ता सुधार की गति में तेजी और भारत का वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता के स्तर पर लाया जा सके।

स्वयं

युवा मण्डलों के लिए सक्रिय शिक्षण का अध्ययन वेब स्वयं एक व्यापक शैक्षिक ढांचे के साथ एक राष्ट्रीय मंच पर एक वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पहल है। यह सम्मेलित मंच शिक्षकों द्वारा बड़े स्तर पर उपयोग के लिए इंजीनियरिंग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के गठन, समुचित प्रमाणन तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात तुरंत ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।

डिजिटल निक्षेपागार

छात्रों के हाथर शिक्षा संस्थाओं और निष्केतओं को कैंडिडेट्स के डिग्री प्रमाणपत्र के लिए प्रतिभूति डिपॉजिटरी की तर्ज पर विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्रों, कॉलेज डिग्रियों, शैक्षणिक पुरस्कारों और अंक तात्कालीन संबंधी एक डिजिटल डिपॉजिटरी (Digital Depository) की स्थापना किया गया है। यह उनकी प्रामाणिकता के वैधीकरण, सुरक्षित संचयन और आसानी से पुनः प्राप्ति में सहायक होगा।

कुल नेट पोषण

किसी बच्चे के 'कुल नेट पोषण' की परिभाषा कुल परिणाम के रूप में निम्न प्रकार से दी जाती है— (क) गर्भावस्था के दौरान माँ के गर्भाशय में मौजूद पोषण एवं स्तनपान के दौरान। (ख) खाद्य की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता जो 6 से 24 माह तक माँ के शरीर में दूध बनाने में पूरक होती है। (ग) बीमारी तथा संक्रमण के कारण ऊर्जा की कुल क्षति एवं पोषक तत्वों का शरीर में कम मात्रा में अवशोषण।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 1995 में कौन-सा अभियान शुरू किया गया, जो सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केन्द्रित है? - **सुगम्य भारत अभियान**
- केंद्र सरकार ने 30 मार्च, 2016 को अपने अग्रणी 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत किस सूचकांक का प्रारंभ किया, जो उद्योग और कॉर्पोरेट स्वेच्छा से कार्यस्थल को दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य बनाने के लिए अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करेगा? - **समावेशी और सुगम्यता सूचकांक**
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1999 से दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की जा रही है। इसकी संशोधित योजना कब से लागू है? - **1 अप्रैल, 2018**

अल्पसंख्यक वर्ग

- किस नाम से अल्पसंख्यकों के लिए एक एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका योजना की शुरुआत की गई है, जिससे ऐसे युवाओं को भी रोजगार मिलने में मदद होगी, जिनके पास औपचारिक स्कूल परित्याग प्रमाणपत्र नहीं हैं? - **नई मंजिल**
- अल्पसंख्यकों की पारम्परिक कला/शिल्प को समृद्ध विरासत के संरक्षण और परम्परागत कारीगरों की क्षमता निर्माण हेतु 14 मई, 2015 को चारागसी में उस्ताद योजना की शुरुआत की गई। उस्ताद का पूरा नाम क्या है? - **अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/क्राफ्ट्स फॉर डेवेलपमेंट**
- केंद्र सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य पारसी आबादी के गिरावट को काम करना, उनकी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसियों के आबादी में वृद्धि करना है? - **जिओ पारसी योजना**
- मानस एक कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण ढांचे को स्थापित करना है तथा मौजूदा व्यवसायों के विस्तार और नए व्यवसायों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक समुदाय और उनकी कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रियायती ऋण भी प्रदान करना है। मानस का पूरा रूप क्या है? - **मौलाना आजाद नेशनल अकादमी फॉर स्किल्स (MANAS)**
- अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच नेतृत्व विकास के लिए वर्ष 2012-13 में कौन-सी योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के साथ ज्ञान प्रकरण और तकनीक प्रदान करके अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करना है? - **नई रोशनी**
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सहायता से कहाँ भारत के प्रथम **गरीब नवाज कौशल विकास केन्द्र** का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए अल्पकालिक नौकरी उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करना है? - **हैबराबाद में**
- भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बद्ध विरासत और संस्कृति की प्रदर्शनी, अनुसंधान और विकास का संरक्षण करने के उद्देश्य से अरबी भाषा से अंग्रेजी, मेडिसिन, गणित और साहित्य के विषयों पर मध्ययुगीन काल के दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई है? - **हमारी धरोहर योजना**
- अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की कौन-सी योजना प्रारंभ की गई है? - **नया सवेरा**

राष्ट्रीय रूबन मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के कुरुष्वात नामक स्थान से राष्ट्रीय रूबन मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रूबन मिशन 'ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं' से युक्त क्लस्टर आधारित विकास करने में सक्षम होगा। यह मिशन रूरल (ग्रामीण) और अर्बन (शहरी) दोनों को मिलाकर संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देशभर में 2019-20 तक 300 स्मार्ट गांवों के एक क्लस्टर का विकास करना और वहां शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं योजना (PURA) का स्थान ग्रहण किया है। यह एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है। इन क्लस्टरों का विकास मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों, कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता के लिए किया जा रहा है। इसमें PPP मॉडल को वरीयता दी जायेगी।

क्रय शक्ति समता (पीपीपी)

क्रय शक्ति समता (PPP: Purchasing Power Parity) घरेलू बाजार में वस्तु एवं सेवाओं की उसी मात्रा की खरीद के लिए अपेक्षित किसी देश की मुद्रा की यूनिटों का संख्या का घातक है जितनी कि एक अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में खरीद सकेगा। इस तरह संबंधित बाजारों में विभिन्न मुद्राओं के बीच क्रय शक्ति विभेदक का समायोजन किया जाता है।

निर्धनता जाल

वह स्थिति निर्धनता जाल (Poverty Trap) कहलाती है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सरकार से रहत पाने वाला व्यक्ति रोजगार की तलाश करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे जो रोजगार प्राप्त होगा, उसका पारिवारिक सरकार से सामाजिक सुरक्षा के

महिला व बाल विकास

- केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने 'शतकीय महिला पहल' योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसी 100 महिलाओं को चुना जायेगा, जिन्होंने पूरे देश में समुदाय और राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान किया है? - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को किस स्थान से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया? - **पानीपत, हरियाणा**
- बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए सरकार ने लघु बचत योजना शुरू की है। इस योजना का क्या नाम रखा गया है? - **सुकन्या समृद्धि योजना**
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर किस वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खोला जा सकेगा? - **बस वर्ष**
- 19 अप्रैल, 2016 को औपचारिक रूप से 61 अतिरिक्त जिलों में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कॉर्पस के साथ यह योजना देशभर के कितने जिलों में शुरू की गई? - **100 जिलों में**
- समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत किस वर्ष प्रारम्भ की गई? - **वर्ष 1975 में**
- राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना-सबला के तहत बालिकाओं (11-18 वर्ष) को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के साथ किन दो योजनाओं को भी जोड़ दिया गया है? - **एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) और किशोरी शक्ति योजना (KSY)**
- मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार करने वाली अथवा इसी प्रकार की किसी योजना की पात्र महिलाओं को छोड़कर सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए तीन किस्तों में कितनी नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है? - **6000 रुपये**
- 1 अप्रैल, 2017 को मातृत्व लाभ संशोधित कानून देशभर में लागू हो गया। इसके तहत सरकार ने वैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? - **26 सप्ताह**
- एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारण तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 9046.17 करोड़ रुपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से किस मिशन की शुरुआत की? - **राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)**
- केंद्र सरकार ने देशभर में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने तथा कई पहलों के माध्यम से बच्चों के लिंग अनुपात में सुधार, नवजात बालिका शिशु के बचपन में सुधार, लड़की को शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की है। यह योजना किस अवधि के लिए कार्यान्वित की गई है? - **2017-18 से 2019-20 तक**

अंतर्गत प्राप्त हो रहे भुगतान से भी कम होगा। अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि निर्धन व्यक्ति काम करने की अपेक्षा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भत्ता लेना अधिक उपयुक्त समझते हैं।

सापेक्षिक गरीबी

सापेक्षिक गरीबी के तहत जनसंख्या के विभिन्न आय वर्ग, चतुर्थांश या दशांश के संबंध में आय संबंधी अनुमान लिये जाते हैं तथा आबादी के निचले 5 से 10% आय समूह की तुलना ऊपरी 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है तथा इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक गरीबी की स्थिति प्रदर्शित करती है। यह अवधारणा स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है।

निरपेक्ष गरीबी

सापेक्षिक गरीबी से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि गरीब लोगों की मात्रा क्या है। इस कमी को दूर करने के लिए निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को अपनाया जाता है। इसके तहत एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें गरीब कहा जाता है। गरीबी रेखा इसी प्रकार की अवधारणा है। इसे हेंड काउंट विधि भी कहा जाता है। निरपेक्ष प्रतिमान का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस के प्रथम महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया था।

लॉरेंज वक्र

आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र, लॉरेंज वक्र (Lorentz Curve) कहलाता है। इसको 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। जब किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- प्राकृतिक आपदा से बेघर हुई विधवाओं, एचआईवी व एड्स से पीड़ित महिलाओं, जेल से छोड़ी हुई कैदी महिलाओं, घर से निकाली गई महिलाओं व प्रताड़ित किए गए स्थानों से बचकर या भागकर आयी लड़कियों, घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं आदि की सहायता के लिए कौन-सी योजना चलायी जा रही है? - **स्वाधार गृह योजना**
- इस योजना के तहत स्वाधार गृह में घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं एक वर्ष तथा दूसरे वर्ग की महिलाएं तीन वर्ष तक रह सकती हैं। वृद्ध महिलाएं, जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है, वे कितने समय तक इस स्वाधार गृह में रह सकती हैं? - **पांच वर्ष**
- मार्च 2008 में प्रारंभ धनलक्ष्मी स्कीम कुछ विशेष परिस्थितियों को पूरा करने के लिए लड़कियों के परिवार को नकद हस्तांतरण प्रदान करती है ताकि वे लड़कियों को शिक्षित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। राज्यों सरकारों द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने के कारण इसको कब से बंद कर दिया गया?

- 1 अप्रैल, 2013 से

- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर, 2017 को किस पोर्टल को लांच किया गया, जिसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाना है?

- **SHe बॉक्स (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स)**

- नारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो महिला नागरिकों को सरकारी योजनाओं और पहलों या महिलाओं के बारे में जानकारी के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है। नारी का पूरा नाम क्या है?

- **National Repository of Information for Women**

शिक्षा क्षेत्र

- तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 11 नवंबर, 2014 को शिक्षा को गांवों से जोड़ने तथा समावेशी विकास के लिए किस योजना का शुभारंभ किया?

- **राष्ट्रीय उन्नत भारत योजना**

- किस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर साल चार हजार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी?

- **'प्रगति' योजना**

- 'सक्षम' योजना के तहत तकनीकी शिक्षा में किन छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल एक हजार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी?

- **विकलांग छात्रों को**

- 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार कौन-सा अभियान 2000-01 से प्रारंभ किया?

- **सर्व शिक्षा अभियान**

- एनएईसीएल द्वारा किस अभियान को राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (NCLP) में समाहित करने का फैसला किया गया?

- **सर्व शिक्षा अभियान**

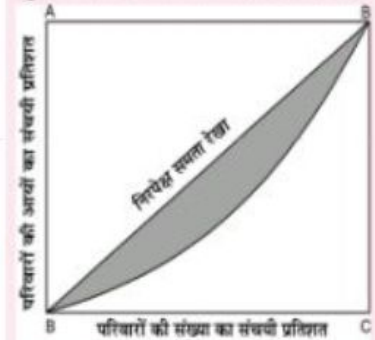
- शिक्षा के परिणामों में वृद्धि करने के लिए 'पढ़े भारत बढ़े भारत' कार्यक्रम में इस तरीके से व्याकरण एवं गणित के शिक्षण में पठन और लेखन में रुचि पैदा करने हेतु भाषा के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई?

- **26 अगस्त, 2014 को**

- यूजीसी ने शैक्षिक वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए किस नाम से एक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है, जिसके तहत छात्रों को प्रतिमाह 3500 से 5000 रुपये के बीच छात्रवृत्ति दी जाएगी?

- **ईशान उदय**

50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत परिवारों को आय का कितना भाग मिल रहा है तथा 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत धनी लोगों को कुल आय का कितना भाग मिल रहा है।



लॉरेंज वक्र समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा, विषमता भी उतनी अधिक होगी, जैसा रेखाचित्र में प्रदर्शित है। स्पष्ट है कि लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। यदि सम्पूर्ण आय किसी एक व्यक्ति के पास हो तो पूर्ण असमान आय वितरण होगा और इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा BA होगी।

गिनी गुणांक

आय या सम्पत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। इसको इटली के अर्थशास्त्री कोरैडो गिनी ने विकसित किया। यदि गिनी गुणांक का मान 1 है, तो इसका आशय यह हुआ कि एक ही व्यक्ति के पास समस्त आय केंद्रित है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी ही अधिक होगी। यदि गिनी गुणांक का मान शून्य है, तो इसका आशय हुआ कि समाज में आर्थिक विषमता नहीं है। गिनी गुणांक वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात को व्यक्त करता है।

- मध्याह्न भोजन योजना देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में आरंभ की गई, जिसके तहत वर्ष 1997-98 तक देश के सभी ब्लॉकों शामिल कर लिया गया। इस योजना का न केवल बच्चों के अधिक नामांकन, बल्कि नियमित छात्र उपस्थिति के रूप में काफी प्रभाव पड़ा है। इस योजना को कब प्रारंभ किया गया?

- 15 अगस्त, 1995 को

- अध्यापकों एवं शिक्षण के संबंध में जारी विभिन्न कदमों में तालमेल पैदा करने के लिए एक 'अम्ब्रेला योजना' आरम्भ की गई। यह मिशन अध्यापकों, शिक्षण, अध्यापक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन से सम्बद्ध सभी मुद्दों को हल करेगी। इस मिशन का क्या नाम रखा गया है?

- चं. भवन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण मिशन

- वर्ष 2015 में देश के लिए प्रासंगिक 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की प्रमुख अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है?

- इम्प्रिंट इंडिया (IMPRINT: Impacting Research INnovation and Technology)

(दस क्षेत्र हैं- स्वास्थ्य, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, धारणीय आवास, नैनो प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, जल संसाधन एवं नदी प्रणाली, उन्नत पदार्थ, विनिर्माण, रक्षा तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन)

- इम्प्रिंट-2 इंडिया कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके तहत किन दो मंत्रालयों ने एक साथ मिलकर एक कोष का निर्माण किया है, जिसमें उद्योग जगत से और अन्य मंत्रालयों से सहयोग मिलने की पूरी सम्भावना है?

- विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय

कौशल विकास

- श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर, 2014 को श्रम जयंती कार्यक्रम की घोषणा की। इस योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है?

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय

- केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के तहत होने वाली प्रगति पर नजर रखने हेतु 20 जनवरी, 2015 को दिल्ली में कौन-सी प्रणाली लांच की?

- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

- आम बजट 2015-16 के तहत भारत में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा वैज्ञानिक शोध की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाने हेतु किस मिशन की घोषणा की गई?

- अटल नवाचार मिशन

- अटल नवाचार (नवप्रवर्तन) मिशन को देशभर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस आयोग ने शुरू किया था?

- नीति आयोग

- किस तकनीक का उद्देश्य कौशल विकास करना तथा पारम्परिक शिल्प तथा हस्तशिल्प में कार्यरत व्यक्तियों की आजीविका के साधन के रूप में आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि करके डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी का उन्मयन करना है?

- युक्ति

- औद्योगिक समूहों के माध्यम से जागरूकता लाने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत करने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में किस योजना की शुरुआत की गई?

- स्ट्राइव योजना

सेन निर्देशांक

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता (1998) प्रो. अमर्त्य सेन ने एक नई विधि का विकास किया है, जिसको सहायता से गरीबी की गहनता (Intensity of Poverty) ज्ञात की जाती है। इसको सेन निर्देशांक या सेन का गरीबी गुणांक कहा जाता है। प्रो. सेन का मानना है कि गरीबी की सही तस्वीर जानने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नहीं गिनना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की आय गरीबी रेखा से कितनी नीचे है। उनके मुताबिक गरीबों की आय की गरीबी रेखा से गिरावट को भारीकृत करके गरीबी को नापा जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि गरीबी रेखा को 1000 रुपये प्रति माह आंका गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसके नीचे के सभी लोग गरीब हैं। इससे ये पता नहीं चलता कि इन गरीबों में भी सबसे गरीब और कम गरीब कौन है। यदि इनकी आय का अवरोही क्रम बनाया जाए, जैसे- 1000, 999, 998, 997, 996... तो इस क्रम में जो व्यक्ति जितना ऊपर होगा वह उतना ही कम गरीब होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है, जिसको 15 जुलाई, 2015 को लांच किया गया। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को सक्षम बनाना है जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिले। इसके तहत पहले सीखने के अनुभव या कौशल के साथ व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और पूर्व सीखने की मान्यता (RPL: Recognition of Prior Learning) के तहत प्रमाणित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण और आकलन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से लागू की जाएगी।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- औद्योगिक संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को प्रवृत्त करने तथा वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2015 में किस योजना की शुरुआत की गई? - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संस्करण-2 (2016-20) में 'नियोजन खोज' का अधिवैसात्मक उपबंध किया गया है।)
- प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र, 2015 का उद्देश्य उच्चाकांक्षी आदर्श प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक जिले में खोलना है। जून 2019 तक कितने प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? - 851
- 15-35 आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं (अजा/अजजा/महिला 45 वर्ष तक) के लिए औपचारिक शिक्षा एवं विपणन कौशल की कमी, जैसे- कौशल अंतराल को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ 25 सितंबर, 2014 को कौन-सी योजना प्रारंभ की गई? - दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
- 'उद्दान' के नाम से एक विशेष उद्योग पहल को किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया जा रहा है? - जम्मू व कश्मीर

स्वास्थ्य व स्वच्छता

- स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बहुत कम है। भारत में विश्व की 17% जनसंख्या रहती है। इस अनुपात में वर्ष 2018-19 के दौरान यहां कुल बीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया गया? - मात्र 1.5%
- स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2019 में गांधीजी की 150वीं जयंती तक पूरे देश को शौचालय सुविधा से युक्त और खुले में शौच को प्रवृत्ति से मुक्त करना है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई? - 2 अक्टूबर, 2014 को
- अप्रैल 2018 में प्रारंभ की गई किस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का नकदरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार या 50 करोड़ लोग इसका प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे? - आयुष्मान भारत योजना
- आयुष्मान भारत योजना के दो घटक हैं- पहला, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र (Health and Wellness Centre) तथा दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (National Health Protection Scheme)। पूरे देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र खोले जायेंगे, जो आवश्यक दवाएं और जांच की सुविधाएं निःशुल्क देंगे। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2018 को कहा इस योजना के तहत पहले स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन किया? - बीजापुर जिला, छत्तीसगढ़
- भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में कौन-सा मिशन शुरू किया, जिसके तहत उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है? - मिशन इंड्रधनुष
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के केंद्र सरकार ने 9 जून, 2016 को किस योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हर महीने 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल निःशुल्क प्रदान करना है? - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना
- 4डी (Defects at birth, Deficiencies, Diseases, Disability) पर नियंत्रण हेतु बच्चों की जांच और निःशुल्क उपचार के लिए फरवरी 2013 में किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)

अनैच्छिक बेरोजगारी

बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें लोग प्रचलित या उससे कुछ कम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार रहते हैं, परंतु कुल प्रभावी मांग में कमी के कारण उनको रोजगार नहीं मिलता है, अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment) कहलाती है।

ऐच्छिक बेरोजगारी

ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते अथवा जो प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं करना चाहते उन्हें ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी की ऐसी स्थिति ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। वे सभी लोग जो काम चाहते हैं उन्हें प्रचलित मजदूरी पर काम मिल जाये तो इसे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कहा जाता है।

खुली बेरोजगारी

जब काम ढूंढने पर भी लोगों को काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, जो काम की तलाश में दर-दर का ठोंकरें खाते फिरते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है।

चक्रीय बेरोजगारी

आर्थिक क्रियाओं में उतार-चढ़ाव के कारण पैदा होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) कहलाती है। इसमें आर्थिक विकास की विभिन्न दशाएं सम्मिलित होती हैं। अर्थव्यवस्था में जब मंदी की स्थिति आती है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है तथा आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ यह बेरोजगारी स्वतः सम्भ्रत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी बेरोजगारी समग्र मांग में कमी और निष्क्रिय उत्पदन क्षमता के कारण होती है और मांग में वृद्धि के साथ-साथ खत्म हो जाती है। ऐसी बेरोजगारी विकसित देशों में सबसे ज्यादा पायी जाती है।

- स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10-19 आयु वर्ग के किशोरों के लिए यौन, प्रजनन स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, चोट लगने और हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित) पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय-स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की शुरुआत कब की? - 7 जनवरी, 2014

निर्धनता एवं विषमता

- अच्छे जीवन स्तर के मुकाबले निम्न जीवन स्तर के आधार पर निर्धनता की कल्पना की जाती है। इस लिहाज से निर्धनता किस प्रकार की अवधारणा है?
- एक सापेक्षिक अवधारणा
- जुलाई 1962 में योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति ने इस बात का अनुमान लगाने का प्रयास किया कि किस राष्ट्रीय आधार पर गरीबी को परिभाषित किया जाये?
- न्यूनतम उपभोग स्तर
- प्रायः न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता रेखा निर्धारित किया जाता है। भारत में योजना आयोग द्वारा किस वर्ष इसे परिभाषित किया गया? - वर्ष 1973-74 में
- भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर किया जाता है?
- खुराक में कैलोरी या मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आधार पर
- योजना आयोग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि 2435 कैलोरी (लगभग 2400 कैलोरी) का उपभोग करता है, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। शहरी क्षेत्रों के लिए यह मापदंड कितने कैलोरी का है?
- 2100 कैलोरी (लगभग 2095 कैलोरी)
- सातवें वित्त आयोग (1978) ने गरीबी रेखा कौन-सी अवधारणा प्रतिपादित की, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक निजी व्यय तथा शिक्षा, प्रशासन आदि पर मासिक सार्वजनिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया?
- विस्तारित गरीबी रेखा
- विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की आय 1.90 से कम है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। इसे कौन-सी रेखा कही जाती है?
- अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने गरीबी रेखा की परिभाषा को संशोधित करते हुए इसे वर्ष 2014 में कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया? - 1.51 डॉलर
- वर्ष 1989 में गठित लकड़ावाला समिति के आकलन के मुताबिक, वर्ष 1993-94 में देश की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा था?
- लगभग 36 प्रतिशत
- लकड़ावाला समिति के निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 1993-94 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाली आबादी की प्रतिशतता कितनी थी?
- क्रमशः 37.27 और 32.36
- गरीबी रेखा के आकलन के लिए गठित प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में प्रस्तुत की। इस समूह ने एमपीसीई के तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर 2004-05 में गरीबी रेखा की गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपये की। इसने शहरी क्षेत्रों के लिए यह राशि कितनी रखी?
- 579 रुपये
- योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2009-10 हेतु गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात को अद्यतन किया। इसने एमपीसीई के तौर पर अखिल भारत के लिए 2009-10 में गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः कितनी राशि का अनुमान लगाया?
- क्रमशः 673 और 860 रुपये

मौसमी बेरोजगारी

प्राकृतिक जलवायु तथा मौसम संबंधी कारणों से मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है। मौसमी बेरोजगारों का मौसम समाप्त होने के बाद की कुछ अवधियों में उत्पादन कार्य न होने के कारण कार्य से हटना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में पायी जाती है। जोतई, बोवाई, कटाई जैसे कार्यों के समय श्रमिकों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन ढीले मौसम में वे बेरोजगार हो जाते हैं।

संरचनात्मक बेरोजगारी

किसी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण ऐसी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। जब किसी देश के निर्यात व्यापार में कमी अथवा गिरावट होती है, तो यह स्थिति संरचनात्मक परिवर्तन की होती है। इसके फलस्वरूप निर्यात उद्योगों में जनित बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। भारत और विकासशील देशों में इस प्रकार का बेरोजगारी देखने को मिलता है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी

प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) से आशय यह है कि यदि किसी उत्पादन क्षेत्र से कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाये तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसे श्रमिकों को छिपे हुए बेरोजगार की संज्ञा दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मात्रा अधिक होती है। ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यह अल्प बेरोजगारी का एक विशेष रूप है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 1936 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मंदी के दौरान अधिक उत्पादक प्रयोग से कम उत्पादक प्रयोग की ओर श्रमिकों के चक्रीय हस्तांतरण के लिए किया था। रेंगर नक्स ने इसको 'अदृश्य बचत संभावना' तथा पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में देखा।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- तेंदुलकर समिति के उक्त आंकड़ों के आधार पर, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी में 2004-05 में 37.2 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में कितनी रह गई? - **मात्र 29.8 प्रतिशत**
- ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट, 2018 के मुताबिक भारत ने 2005-06 से 2015-16 के बीच के 10 वर्षों के दौरान 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005-06 में 55% गरीब थे, जो 2015-16 में कम होकर कितना रह गए? - **लगभग 28%**
- योजना आयोग ने जून 2012 में गरीबी के मापन की विधि की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया? - **डॉ. सी. रंगराजन**
- निर्धनता जाल की स्थिति में किसी व्यक्ति को रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक सरकारी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त राशि से अधिक होता है या कम? - **कम**
- उस स्थिति को क्या कहा जाता है, जब निर्धन व्यक्ति काम करने की अपेक्षा सामाजिक सुरक्षा के तहत भत्ता लेना अधिक उपयुक्त समझता है? - **निर्धनता जाल (Poverty Trap)**
- आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र किस नाम से जाना जाता है? - **लॉरेंज वक्र (Lorentz curve)**
- जब सभी आय प्राप्तकर्ताओं का आय में हिस्सा बराबर रहे, अर्थात् 25 प्रतिशत लोगों के पास 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत लोगों के पास 10 प्रतिशत आय का हिस्सा हो तो लॉरेंज वक्र के प्राक में एक विशिष्ट प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। इसको क्या कहा जाता है? - **निरपेक्ष समता रेखा**
- जब लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा, विषमता भी उतनी अधिक होगी या कम? - **अधिक**
- आय या सम्पत्ति के वितरण में व्याप्त विषमता की सांख्यिकी माप को किस गुणांक के नाम से जाना जाता है? - **गिनी गुणांक (Coefficient of Ginni)**
- जब गिनी गुणांक का मान 1 हो तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक ही व्यक्ति के पास समस्त आय केंद्रित है, अर्थात् गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी ही अधिक होगी। यदि गिनी गुणांक का मान शून्य होगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा? - **समाज में आर्थिक विषमता नहीं है**
- वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? - **गिनी गुणांक**
- हैड काउंट विधि के तहत किसी देश के कुल निधनों तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करने पर निर्धनता का संख्या आधारित गुणांक प्राप्त होता है। इस गुणांक का मान कम होने पर निधनों की संख्या कम होती है या अधिक? - **कम**
- निर्धनता की गहनता ज्ञात करने के लिए 1998 में प्रो. अमर्त्य कुमार सेन ने एक विधि का प्रतिपादन निर्धनता सूचकांक ज्ञात किया। वह निर्देशांक क्या है? - **$P = H[1 + (1 - I) - G]$ (जहाँ P = निर्धनता सूचकांक, H = हैड काउंट रेशियो, I = गरीबी अंतगल अनुपात और G = गरीबी के आय वितरण का गिनी गुणांक)**
- यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के तहत 30 दिनों में सभी वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय का आंकड़ा संग्रह करके निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। जब 365 दिनों में 5 गैर-खाद्यान्न वस्तुओं (कपड़ा, स्थायी वस्तुओं, शिक्षा एवं संस्थागत चिकित्सा व्यय) पर उपभोक्ता व्यय के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है, तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? - **डिपेंडेंट रिकॉल पीरियड**

प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी

ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है। इस प्रकार की बेरोजगारी के उत्पन्न होने का कारण अर्थव्यवस्था विशेषतः श्रम बाजार में निरंतर परिवर्तन का न होना तथा बदली हुई परिस्थितियों में उनका तात्कालिक समायोजन का न होना है। श्रमिकों के एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर कई प्रकार की कठिनाइयाँ-व्यावसायिक, भौगोलिक, स्थान तथा भाषा संबंधी आती हैं। अतः नए उत्पादन क्षेत्र में वे अपने को जब तक समायोजित नहीं कर लेते, तब तक वे बेरोजगार रहते हैं। इस अस्थायी स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी तकनीकी में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के कारण भी होती है। यह बेरोजगारी विशेषकर विकसित देशों में पायी जाती है।

तकनीकी बेरोजगारी

ऐसी बेरोजगारी उत्पादन में तकनीकी विधियों को लागू करने से पैदा होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि तथा उद्योग दोनों में ही हो सकती है। उदाहरणार्थ, किसी कारखाने में आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण की योजनाएं लागू की जायें तो उसमें पहले की अपेक्षा कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। फलस्वरूप बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। इसी प्रकार यदि कृषि का यंत्रीकरण किया जायें, तो अधिकांश कृषक बेरोजगार हो जायेंगे। इसी कारण आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकरण का सदैव विरोध किया जाता है।

शिक्षित बेरोजगारी

जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो यह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। आज प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति शारीरिक कार्य से नफरत करता है तथा 'सफ़ेद कॉलर' वाले

- किसी भी देश की जनसंख्या का उस भाग को क्या कहा जाता है, जो निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करता है?
- निर्धनता अनुपात (Poverty Ratio)
- अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक द्वारा गरीबी पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के अंत तक दुनिया में अति गरीबी की आबादी घटकर 10% से भी कम रह जायेगी। विश्व बैंक ने अति गरीबी मापने के नया पैमाना प्रतिदिन 1.25 डॉलर (लगभग 75 रुपये) से बदलकर कितना कर दिया है?
- मात्र 1.90 डॉलर प्रतिदिन
- एशियाई विकास बैंक (एडीवी) ने गरीबी रेखा की परिभाषा को संशोधित करते हुए कितना कर दिया है?
- मात्र 1.51 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

बेरोजगारी

- वह सामाजिक-आर्थिक स्थिति जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर या उससे भी कम पर कार्य करने की इच्छा रखने के बावजूद उसे कार्य नहीं मिलता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है?
- बेरोजगारी
- जब कोई श्रमिक जानबूझकर प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम नहीं करता है, तो बेरोजगारी के उस स्वरूप को क्या कहा जाता है?
- ऐच्छिक बेरोजगारी
- भारत में बेरोजगारी का स्वरूप ऐच्छिक ज्यादा है या अनैच्छिक?
- अनैच्छिक बेरोजगारी
- जब किसी उत्पादन कार्य में से कुछ श्रमिकों को हटा देने के बावजूद उत्पादकता यथावत बनी रहती है, तो अल्प बेरोजगारी के उस प्रकार को क्या कहा जाता है?
- प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment)
- प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पायी जाती है?
- कृषि क्षेत्र
- प्राकृतिक जलवायु तथा मौसम की वजह से कुछ समय के लिए श्रमिकों को उत्पादन कार्य के न होने के कारण रोजगार से हटना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यह मुख्यतः किन क्षेत्रों में पायी जाती है?
- कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में
- श्रमिक एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और व्यावसायिक, भौगोलिक, स्थान और भाषा संबंधी कठिनाइयों से जब तक समायोजित नहीं कर लेते, तब तक वे अल्प अवधि के लिए बेरोजगार रहते हैं। इस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है?
- धर्मणात्मक बेरोजगारी
- जब किसी देश के निर्यात व्यापार में कमी अथवा गिरावट होती है, तो इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन के कारण निर्यात उद्योगों में किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है?
- संरचनात्मक बेरोजगारी
- आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है?
- चक्रीय बेरोजगारी
- भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो रोजगार की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है?
- खुली बेरोजगारी
- जब किसी कारखाने में आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण की योजनाएं लागू की जाती हैं तो उसमें पहले की अपेक्षा कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कृषि का यंत्रीकरण किया जाये तो अधिकांश कृषक बेरोजगार हो जायेंगे। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है?
- तकनीकी बेरोजगारी

कार्य' की तलाश में मारा-मार फिरता है। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। शिक्षित बेरोजगार प्रायः शहरों में पड़े जाते हैं। शिक्षित प्रामाण्य भी रोजगार की तलाश में अकसर शहरों में भटकते रहते हैं। ऐसा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण होता है, जिसका व्यावसायिक पहलु कमजोर होता है।

सनसेट क्लॉज

'सनसेट क्लॉज' का तात्पर्य है किसी भी सरकारी योजना को लागू करने के समय ही यह तय कर लेना कि उसे कब पूरी होनी है। भारत में अब सरकारी योजनाएं इसी कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं। सभी स्वीकृत योजनाएं 'परिणाम समीक्षा' रिपोर्ट के साथ सम्पन्न होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका फायदा लाभार्थी को मिले। सनसेट क्लॉज से 600 से अधिक ऐसे अधिनियम समाप्त हो जायेंगे। ऑस्ट्रेलिया में यह प्रावधान लागू है।

एर्गोनॉमिक्स

एर्गोनॉमिक्स (Ergonomics) अर्थशास्त्र की वह शाखा है, जिसमें किसी श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है।

उपभोग फलन

किसी भी उपभोक्ता का उपभोग फलन (Consumption Function) उसकी आय पर निर्भर करता है। आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है। परंतु एक सीमा के बाद आय में वृद्धि के बाद भी उपभोग स्थिर हो जाता है।

अचल लागत

उत्पादन के सापेक्ष अपरिवर्तित रहने वाली लागतें अचल लागत या स्थिर लागत (Fixed Cost) कहलाती हैं। किराये का भुगतान, प्रबंधक का वेतन, पूंजी, ब्याज आदि स्थिर लागत के अंग हैं।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- वह कार्य जिसको प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति करना चाहता है और जिसमें वह शारीरिक कार्य करना पसंद नहीं करता, कहलाता है? - सफेद कॉलर वाले कार्य
- किसी भी देश की जनसंख्या का वह प्रतिशत भाग या दर जो कार्यरत हो या जिसे रोजगार प्राप्त हो, कहलाता है? - कार्य बल सहभागिता दर (Work Force Participation Rate)
- जनगणना, 2001 के अनुसार, भारत में कार्य सहभागिता दर 39.1 प्रतिशत थी। इनमें पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी थी? - मात्र 51.7 प्रतिशत
- जनगणना, 2001 के अनुसार, मिजोरम में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक 52.6 प्रतिशत थी। सबसे कम मात्र 25.3 प्रतिशत कार्य सहभागिता दर किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में थी? - लक्षद्वीप
- किसी देश की जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग (आर्थिक रूप से सक्रिय) का वह प्रतिशत भाग या दर क्या कहलाता है? - श्रम बल सहभागिता दर (Labour Force Participation Rate)
- भारत में वर्ष 2011 में श्रम बल सहभागिता दर कितनी थी? - मात्र 55 प्रतिशत
- भारत में बेरोजगारी की समस्या का पहचान तथा रोजगारपरक आर्थिक विकास रणनीति तथा सक्रिय रोजगार नीति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई? - पांचवीं पंचवर्षीय योजना
- बेरोजगारों की संख्या जो वर्ष 1956 में 50 लाख थी, वर्ष 1973-74 में बढ़कर 100 लाख से अधिक हो गई। इसीलिए पांचवीं योजना में गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए किस प्रकार की नीति अपनायी गई? - प्रत्यक्ष प्रहार की नीति
- वर्ष 1973 में बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन, इसकी माप तथा समाधान के उपाय के संबंध में संसुति के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई, जिसने बेरोजगारी की माप के संबंध में तीन धारणाओं-सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू (दैनिक) स्टेटस, जिसे एनएसएसओ के 27वें चक्र से प्रयोग में लाया जा रहा है, का प्रतिपादन किया? - धी. भगवती
- बेरोजगारी की माप के संबंध में उक्त तीन धारणाओं को एनएसएसओ के किस चक्र से प्रयोग में लाया जा रहा है? - 27वें चक्र से
- आईआरडीपी, एनआरडीपी, ट्राइसेम और आरएलईजीपी जैसी रोजगार सृजक योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई? - छठी पंचवर्षीय योजना
- किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार रोजगार को विकास नीति में केंद्रीय स्थान दिया गया और विभिन्न रोजगार सृजक योजनाओं को इस योजना के दौरान भी बनाये रखा गया? - सातवीं पंचवर्षीय योजना
- आईएलओ द्वारा 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक-ट्रेड्स 2018' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर वर्ष 2018 और 2019 में कितनी रहेगी? - मात्र 3.5 प्रतिशत
- भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड रखता है। इसके अनुसार, वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी की दर कितनी थी? - मात्र 3.6%

गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम व योजनाएं

- भारत के गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1952 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? - सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme)

औसत लागत

कुल लागत एवं कुल उत्पाद का अनुपात औसत लागत कहलाता है, अर्थात् कुल लागत में कुल उत्पाद से भाग देकर औसत लागत (Average Cost) ज्ञात की जाती है।

औसत उपभोग प्रवृत्ति

आय का वह भाग, जो उपभोग पर व्यय होता है, 'औसत उपभोग प्रवृत्ति' (Average Propensity of Consume) कहलाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए उपभोग और आय का अनुपात निकाला जाता है।

औसत बचत प्रवृत्ति

किसी भी व्यक्ति/फर्म की आय का वह भाग जो बचा लिया जाता है, उसकी दर को औसत बचत प्रवृत्ति (Average Propensity of Saving) की संज्ञा प्रदान की जाती है। औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात होती है।

अचल परिसम्पत्ति

किसी भी व्यक्ति/फर्म की स्थायी सम्पत्ति यथा- भूमि, इमारतें, मशीनरी, फर्नीचर, गाड़ियां आदि अचल परिसम्पत्ति (Fixed Asset) होती है।

उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति

किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume) कहलाता है।

वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात

किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए पूंजी की जितनी अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होती है, उसे वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात (Increasing Capital Output Ratio) कहा जाता है।

मिशन NCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976-77 में देश के कुछ चयनित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP: Integrated Rural Development Programme) का शुभारंभ किया गया। इसको विस्तारित करके देश के सभी विकास खंडों में कब लागू किया गया?
- 2 अक्टूबर, 1980 को
- 15 अगस्त, 1979 को ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (TRYSEM: Scheme of Training Rural Youth for Self Employment) प्रारंभ की गई। इसका अब स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर इसे 1 अप्रैल, 1999 से किस योजना में मिला दिया गया?
- स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
- ट्राइसेम के तहत निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले किस आयु वर्ग के युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?
- 18-35 वर्ष
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP: National Rural Employment Programme) एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया?
- अक्टूबर 1980
- एनआरईपी 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' (FWP: Food for Work Programme) का पुनर्गठित रूप है। एफडब्ल्यूपी को कब प्रारंभ किया गया था?
- वर्ष 1977-78 में
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर अप्रैल 1989 में किस योजना में विलय कर दिया गया?
- जवाहर रोजगार योजना
- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के परिवारों हेतु कम-से-कम 100 दिन का वार्षिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP: Rural Landless Employment Guarantee Programme) का आरंभ किया गया। इस योजना का किस योजना में विलय कर दिया गया?
- जवाहर रोजगार योजना
- अप्रैल 1989 में ग्रामीण विकास तथा रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना (JRY: Jawahar Rojgar Yojna) शुरू की गई। इसके अंतर्गत व्यय की जाने वाली राशि का वहन केंद्र तथा राज्यों के बीच किस अनुपात में किया जाता है?
- क्रमशः 80:20
- जवाहर रोजगार योजना की दो प्रमुख उपयोजनाएं कौन-सी हैं?
- इंदिरा आवास योजना तथा 10 लाख कुआं योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई। यह योजना किस राज्य की रोजगार गारंटी योजना के मॉडल पर आधारित है?
- महाराष्ट्र
- पीएमआरवाई को प्रारंभ में देश के 261 जिलों के 1778 विकास खंडों में लागू किया गया था। इस योजना को कब से पूरे देश में लागू किया गया?
- 31 दिसंबर, 1995 से
- सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम (DAP: Drought Area Programme) की शुरुआत 1973-74 में की गई। वर्तमान में इसको कितने राज्यों के 155 जिलों के 947 विकास खंडों में चलाया जा रहा है?
- 13 राज्यों में
- 1988-89 में प्रारंभ किए गए किस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती का विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाती है?
- कुटीर ज्योति कार्यक्रम
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर, 2002 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
- स्वजनकाल कार्यक्रम

उत्पादन के साधन

अर्थव्यवस्था के मानवीय तथा गैर-मानवीय उत्पादन संसाधन जिन्हें चार शीर्षकों के अंतर्गत बांटा जा सकता है—भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, उत्पादन के साधन (Factors of Production) कहलाते हैं।

लगान

किसी भी उत्पादन साधन को उसकी न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक अदायगी लगान (Rent) कहलाती है। यथा कृषि भूमि पर देय लगान भूमि की उत्पादन साधन आय होती है।

आर्थिक लगान

उत्पादन साधन के स्वामी को न्यूनतम पूर्ति कीमत या साधन की हस्तांतरण कमाई के ऊपर अधिकता के रूप में प्राप्त अदायगी को आर्थिक लगान (Economic Rent) कहा जाता है।

संतुलन कीमत

बाजार में वस्तु की जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर होंगे, मांग और पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन का बिंदु, वह कीमत जिस पर फर्म के लाभ अधिकतम (या हानि न्यूनतम, यदि हानि पर भी उत्पादन करना अनिवार्य है तो) होते हैं, उसे संतुलन कीमत (Equilibrium Price) कहा जाता है।

औसत लागत

उत्पाद की प्रति इकाई औसत लागत (Average Cost) कुल लागत को उत्पाद से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है।

औसत स्थिर लागत

कुल स्थिर लागत को उत्पाद की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर (अचल) लागत (Average Fixed Cost) प्राप्त की जाती है। इसे कुल औसत लागत में से औसत चल लागत को घटाकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1972-73 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? - **त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ARWSP)**
- ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में ज्यादा-से-ज्यादा वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1986 में किस मिशन की स्थापना की? - **राष्ट्रीय पेयजल मिशन (NDWM: National Drinking Water Mission)**
- किस वर्ष राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (RGNDWM) कर दिया गया? - **वर्ष 1991 में**
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी आधारभूत ढांचे और घरों में बिजली उपलब्ध करने के लिए अप्रैल 2005 कौन-सी योजना शुरू की गई? - **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना**
- ग्रामीण स्वच्छता के मामले में राज्यों के प्रयासों को सहयोग देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP: Central Rural Sanitation Programme) लागू किया? - **वर्ष 1986 में**
- केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 1999 में शुरू किए गए समग्र स्वच्छता अभियान (TSC: Total Sanitation Campaign) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2003 में किस पुरस्कार की घोषणा की? - **निर्मल ग्राम पुरस्कार**
- निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से प्रोत्साहित होकर सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी परिवारों के लिए शत प्रतिशत स्वच्छता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ सभी ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय निर्मित कराने के लिए वर्ष 2012 में समग्र स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया? - **निर्मल भारत अभियान (एनबीए)**
- नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक देश को स्वच्छ करने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर, 2014 किस अभियान की शुरुआत की? - **स्वच्छ भारत मिशन**
- मार्च 2007 तक बालश्रम के उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 9 फरवरी, 2004 को नई दिल्ली में किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? - **बालश्रम उन्मूलन पर राष्ट्रीय प्राधिकरण (NAECL)**
- राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को नौकरी जाने, फैक्टरी या संस्थान बंद हो जाने, अधिवृद्ध होने या फिर स्थायी विकलांगता के कारण बेरोजगार होने की स्थिति में छह माह तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सकेगा, जो उनके वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। लेकिन इस योजना में कम-से-कम कितने वर्षों तक अंशदान देना जरूरी है? - **पांच वर्षों तक**
- गांवों से नगरों की ओर पलायन रोकने के लिए लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम (IDSMT) का सूत्रपात किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? - **छठी पंचवर्षीय योजना**
- मेगा शहरों में आधुनिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? - **वर्ष 1993-94 में**
- वर्ष 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना (SEEU: Self Employment to Educated Unemployed Youth) का विलय 1 अप्रैल, 1994 को किस योजना में कर दिया गया? - **जवाहर रोजगार योजना**
- वर्ष 1986 में केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (SEPUP: Self Employment Programme for the Urban Poor) का श्रीगणेश किया गया। वर्ष 1992-93 में इसका विलय किस योजना में कर दिया गया? - **नेहरू रोजगार योजना**

औसत सीमांत लागत संबंध

जब औसत लागत वक्र गिर रहा होता है तो उसका संगत लागत वक्र औसत लागत के नीचे होता है। जब औसत लागत वक्र न्यूनतम पर होता है, तो संगत सीमांत लागत वक्र उसके बराबर होता है। जब औसत लागत वक्र बढ़ रहा होता है, तो उसका संगत सीमांत लागत वक्र उसके ऊपर होता है। इसी को औसत सीमांत लागत संबंध (Average Marginal Cost Relationship) कहा जाता है।

अंतर्निहित लागत

स्वपूर्ति द्वारा किए गए उत्पादन की लागत, जिसको कम्पनी के सामान्यतः लेखे-जोखे में नहीं जोड़ा जाता, अंतर्निहित लागत (Implicit Cost) कहलाती है। उदाहरण के लिए, मालिक पूंजी की पूर्ति भी कर सकता है और फर्म का मैनेजर भी हो सकता है। इन सेवाओं की अवसर लागतें अंतर्निहित लागतें होती हैं।

अचल लागतें

वे लागतें जो उत्पाद के साथ परिवर्तित नहीं होतीं या लागतें जो उत्पाद के परिवर्तित होने पर भी अपरिवर्तित रहती हैं, अचल लागतें (Fixed Costs) कहलाती हैं। उदाहरणतः उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, सम्पत्ति कर, किराये का भुगतान, स्थायी कर्मचारियों की तनखाह का भुगतान आदि।

औसत कुल लागत

कुल लागत को उत्पाद की कुल मात्रा से भाग देकर औसत कुल लागत (Average Total Cost) प्राप्त की जाती है। औसत कुल लागत, औसत अचल लागत और औसत चल लागत के योग के बराबर होती है।

कुल लागत

दिए गए उत्पाद के लिए फर्म की कुल अचल लागत और कुल चल लागतों का योग कुल लागत (Total Cost) कहलाता है।

- 1989 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नेहरू रोजगार योजना (NRY) शुरू की गई। मार्च 1990 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्यों द्वारा किस अनुपात में किया जाता था? - 60:40
- 18 नवंबर, 1995 को प्रधानमंत्री समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (PMIUPEP) का शुभारंभ केरल के कोट्टायम जिले के किस शहरी कस्बे से किया गया? - चेंगना चेरी
- गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवाओं की योजना (UBSP) की शुरुआत वर्ष 1990-91 में की गई। वर्तमान में यह किस योजना की एक उपयोजना के रूप में क्रियान्वित है? - नेहरू रोजगार योजना
- स्वरोजगार उद्यम की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों और अल्प-रोजगार वालों के लिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए 1 दिसंबर, 1997 को भारत सरकार द्वारा कौन-सी योजना प्रारंभ की गई? - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (GJUES)
- शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? - वर्ष 2013-14
- 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना 2 अक्टूबर, 2007 से लागू की गई? - आम आदमी बीमा योजना
- असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (एक यूनिट में पांच से अधिक परिवार नहीं) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) 1 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई। इसे कब से लागू किया गया? - 1 अप्रैल, 2008
- किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की व्यवस्था की गई है जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करते हैं? - असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
- ग्राम सभा द्वारा पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेघर लोगों तथा उन लोगों को जो जीर्ण-शीर्ण तथा कच्चे घर में रहते हैं, घर मुहैया कराने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की शुरुआत कब की गई? - 1 जनवरी, 1996 को
- पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को कब लागू किया गया? - 25 दिसंबर, 2000 को
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) की शुरुआत 2007 में की गई। इस समय यह किस राज्य को छोड़कर 27 राज्यों के उन 272 जिलों, जिनकी पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की गई है, में लागू है? - गोवा
- शहरी अवसंरचना के उन्नयन, आवासों के निर्माण और गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) कब शुरू किया गया? - दिसंबर 2005 में
- झुग्गी बस्तियों में रहने वालों तथा शहरी गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया तथा 1 अप्रैल, 2012 से लागू किया गया? - राजीव आवास योजना (RAY)
- ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आय के सृजन हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में सितंबर 1982 में 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम' का शुभारंभ किया गया। यह योजना किसके वित्तीय सहयोग से चलायी जाती है? - यूनीसेफ, राज्य एवं केंद्र सरकार

कुल स्थिर लागत

फर्म की वह कुल लागत, जो उत्पाद में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती, कुल स्थिर लागत (Total Fixed Cost) कहलाती है।

औसत परिवर्ती लागत

कुल परिवर्ती (चल) लागत को उत्पाद की मात्रा से भाग देकर औसत परिवर्ती लागत (Average Variable Cost) प्राप्त की जाती है। यह औसत कुल लागत में से औसत स्थिर (अचल) लागत को घटाने से प्राप्त मात्रा के बराबर है।

कुल परिवर्ती लागत

वे लागतें, जो उत्पाद के साथ परिवर्तित होती हैं, कुल परिवर्ती या चल लागत (Total Variable Cost) कहलाती हैं। यदि उत्पादन शून्य हो, तो कुल चल लागतें भी शून्य होंगी।

परिव्यय लागत

व्यापार में प्रत्यक्ष मुद्रा लागतें यथा, मजदूरी वेतन, लगान, कच्चे माल पर व्यय की गई मुद्रा को परिव्यय लागत (Outlay Cost) कहा जाता है।

परिसम्पत्ति

वे साधन या बहुमूल्य वस्तुएं, जो व्यक्ति विशेष, परिवार या फर्म के स्वामित्व में हों, परिसम्पत्ति (Assets) कहलाते हैं। नकदी, सम्पत्ति, भूमि का पट्टा, मशीनरी इत्यादि परिसम्पत्तियां हैं।

मूर्त सम्पत्तियां

मूर्त सम्पत्तियां (Tangible Assests) ऐसी सम्पत्तियां होती हैं, जिनको देखा तथा अनुभव किया जा सकता है। यथा, कुर्सी, मेज, कार, स्कूटर, टीवी आदि।

लोच

कामत में परिवर्तन की प्रतिक्रियास्वरूप मांगी गई (पूर्ति की गई) मात्रा में परिवर्तन का अनुपात लोच (Elasticity) कहलाता है।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम' का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है?
- **जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA)**
- विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में केंद्र सरकार ने किस कोष की स्थापना की?
- **राष्ट्रीय महिला कोष (NWF)**
- 2 अक्टूबर, 1993 को केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं में वचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने के लिए किस योजना का शुभारम्भ किया?
- **महिला समृद्धि योजना**
- केंद्र सरकार ने महिलाओं में जागरूकता लाने तथा उनको आय के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ईंदिरा महिला योजना का सुरुवात कब किया?
- **20 अगस्त, 1995 को**
- वर्ष 1970-71 में 3 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, मनोरंजन सुविधाएं और अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
- **बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम**
- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए परंपरागत क्षेत्रों तथा कृषि, पशुपालन, डेयरी, हथकरघा और हस्तशिल्प आदि के परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस वर्ष महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) का शुभारम्भ किया गया?
- **वर्ष 1987 में**
- स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर बालिकाओं की स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री द्वारा बालिका समृद्धि योजना की घोषणा 15 अगस्त, 1997 को की गई। इसका क्रियान्वयन कब से प्रारंभ हुआ?
- **2 अक्टूबर, 1997 से**
- केवल निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2005 से कौन-सी योजना चलायी जाती है, जिसका उद्देश्य मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर पर नियंत्रण स्थापित करके गर्भवती महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है?
- **जननी सुरक्षा योजना**
- महिलाओं की खरीद-फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास तथा उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केंद्र प्रायोजित किस स्कीम का शुभारम्भ 4 दिसंबर, 2007 को किया गया?
- **उज्ज्वला**
- 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को वर्ष के 300 दिन पोषणयुक्त राशन मुहैया कराने के लिए किस योजना को वर्ष 2010 में 200 जिलों में प्रारंभ किया गया?
- **सबला**
- ग्रामीण भारत में मूलभूत सुविधाएं तथा अवसररचना प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2005-06 में भारत निर्माण योजना प्रारम्भ की थी। इसके कुल छः घटक कौन-कौन से हैं?
- **सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतिकरण तथा दूरसंचार सम्पर्क**
- सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी दोनों के जरिए उनको आय सर्जक परिसम्पत्तियां प्रदान करके गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य के साथ 1 अप्रैल, 1999 से किस योजना की शुरुआत की गई?
- **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY)**
- वर्ष 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करने और उन्हें लगातार तब तक संघोषित करने और सहायता देने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2011 में **राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (NRLM)** की शुरुआत की गई ताकि वे दयनीय गरीबी से उबर सकें। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है?
- **आजीविका**

अशोधित जन्म दर

किसी एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate) कहा जाता है।

सामान्य प्रजननता दर

सामान्य प्रजननता दर (General Fertility Rate) का अभिप्राय प्रजनन योग्य आयु वाली प्रति हजार महिलाओं द्वारा जन्मित कुल जीवित शिशुओं की संख्या से है।

शुद्ध प्रजनन दर

शुद्ध प्रजनन दर (Net Reproduction Rate) वह दर है, जिस पर किसी देश की महिला जनसंख्या स्वयं को प्रतिस्थापित करती है। यदि शुद्ध प्रजनन दर एक हो तो देश की जनसंख्या में स्थिरता की प्रवृत्ति होगी। शुद्ध प्रजनन दर के एक से अधिक होने पर जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा एक से कम होने पर जनसंख्या में कमी की प्रवृत्ति पायी जाती है।

व्युत्पन्न मांग

किसी उत्पाद या उत्पादन साधन की मांग, जो किसी अन्य वस्तु जिसके उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता हो, की मांग से व्युत्पन्न हो, व्युत्पन्न मांग (Derived Demand) कहलाती है। उदाहरणार्थ, ईंटों की मांग मकान बनाने की मांग से व्युत्पन्न मांग है और इस्पात की मांग औद्योगिक रूप से कारों की मांग से व्युत्पन्न है।

भारत समावेशी नवाचार कोष

लघु उद्यमियों की वित्तीय और तकनीकी कठिनाइयां दूर करने के ध्येय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) तथा राष्ट्रीय नवाचार परिषद ने 27 जनवरी, 2014 को भारत समावेशी नवाचार कोष के गठन की घोषणा की। इस कोष की शुरुआती पूंजी 500 करोड़ रुपये रखी गई है।

- आजीविका के तहत लाभान्वित लोगों की पहचान के लिए बीपीएल के स्थान पर किसको आधार बनाया गया है?

- पीआईपी (Participatory Identification of Poor)

- महिला किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए एनआरएलएम के एक विशेष कार्यक्रम के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई?

- वर्ष 2010-11 में

- शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) की शुरुआत 1 दिसंबर, 1997 को की गई। इसे कब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) से सम्बद्ध कर दिया गया?

- सितंबर 2013 में

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा), जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) नाम रख दिया गया, के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर अब कितना दिन कर दिया गया है?

- 150 दिन

- 2 फरवरी, 2006 से मनरेगा के तहत प्रारंभ में देश की 200 जिलों को शामिल किया गया था, जिसे 1 अप्रैल, 2008 से बढ़ाकर देश के कितने जिलों तक कर दिया गया है?

- सभी जिलों तक

खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम

- वर्ष 1950 में शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलकर उसे देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में सूखा वाले क्षेत्र, रेगिस्तान, जनजाति बहुल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तथा शहरों की मलिन वस्तियों तक ले जाया गया?

- जून 1992 में

- किस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून, 1997 को शुरू की गई तथा उसे दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया?

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

- टीपीडीएस एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को तीन वर्गों अन्वोदय अन्न योजना वाले परिवार (एएवाई), गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार (बीपीएल) और गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर वाले परिवार (एपीएल)। इनमें से किनको आर्थिक लागत के बराबर कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है?

- एपीएल

- गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत आवंटित अनाज का इस्तेमाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बच्चों और उपेक्षित वर्गों से सम्बद्ध गर्भवती व दुग्धपान करने वाली माताओं को पोषिक भोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों के लिए प्रति छात्र 15 किलोग्राम देने का अनाज आपूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था?

- अक्टूबर 1994

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आने वाले कल्याणकारी संस्थाओं, यथा- भिक्षुकगृहों, नारी निकेतनों आदि की अनाज आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनाज आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?

- वर्ष 2002-03

पीजी स्कीम

कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर और सैकड़ों प्रकार की स्कीमों चलाकर अनेक कंपनियां भड़कले से निवेशकों के हजारां करोड़ रुपयों की हराफेरी कर रही हैं। पीजी, पिरामिड, चैन, लॉटरी व चिटफंड, क्रेडिट नेटवर्क, मल्टीलेवल मार्केटिंग, ग्रुपसेल्स, प्राइज चिप्स, समेकित निवेश इत्यादि स्कीमों बखूबी चलाई जाती हैं। फर्जी कंपनियों द्वारा चलाई गई बेसुमार पीजी स्कीमों व धन जमा योजनाओं के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसे घोटालों की कड़ी में सहारा ग्रुप, शारदा चिटफंड, सत्यम ग्रुप, अर्बतत्व ग्रुप आदि के प्रकरण जगजाहिर हैं। पीजी स्कीम का नामकरण इटली निवासी चार्ल्स पीजी नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ा। उसने वर्ष 1920 में अमेरिका में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय डाक कूपन के नाम पर धोखा देकर तहलका मचा दिया था। पीजी स्कीमों पर लगाम कसने तथा छोटे-छोटे निवेशकों से पैसा लेकर रातोंरात चंपत हो जाने वाली फर्जी कंपनियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से लांकुसभा द्वारा पारित प्रतिभूति कानून (संशोधन) 2014 केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा को प्रभावी अधिकार मिल गया है। इसके अलावा डिफाल्टरों के खिलाफ जांच व अभियोजन में तेजी लाने के लिए मामलों की सुनवाई हेतु मुंबई में विशेष अदालत का गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

10 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) का शुभारंभ किया। इस योजना को देशभर में मत्स्यपालन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यह मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (5 वर्ष की अवधि के

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- आपात आहार कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के वृद्ध, अक्षम व बेसहारा लोगों को विपत्ति के समय भोजन मुहैया कराने का एक अनाज आधारित उपाय है, जिसको सबसे पहले मई 1995 में किस राज्य के पांच जिलों में शुरू किया गया? - ओडिशा
- 15 अगस्त, 1985 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं (कक्षा 8 तक) को पका भोजन मुहैया कराने के लिए मिड-डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? - नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन
- वर्ष 2002 से शुरू किस योजना के तहत कवर किए गए बीपीएल परिवारों में से सबसे निर्धन परिवारों की पहचान कर उन्हें 35 किग्रा अनाज 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल आवंटित किया जाता है? - अंत्योदय अन्न योजना
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2000-01 में किस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धावस्था पेंशन नहीं पाने वाले व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क देने का प्रावधान था? - अन्नपूर्णा योजना
- वर्ष 2002-03 से अन्नपूर्णा योजना को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से मिलकर बने किस कार्यक्रम के साथ राज्यों हस्तांतरित कर दिया गया? - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- जनजातीय मंत्रालय द्वारा 11 राज्यों में किस स्कीम के तहत अनाज बैंक स्थापित किया गया है, जिसको 24 नवंबर, 2004 से खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? - ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम
- भारत की 67 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब अस्तित्व में आया? - 12 सितंबर, 2013 को
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणियाँ रखी गई हैं, पहला- प्राथमिकता वाला समूह तथा दूसरा सामान्य समूह। इसमें क्रमशः 46 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत लाभार्थी हैं। पहली श्रेणी में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से दिया जायेगा। सामान्य समूह के लाभार्थी को यह अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के कितने प्रतिशत कम कीमत पर प्राप्त होंगे? - मात्र 50 प्रतिशत
- गर्भवती महिलाओं को उक्त कानून के दायरे में शामिल करने के लिए उन्हें गर्भावस्था में तथा उसके बाद के 6 माह तक कितनी सहायता राशि प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है? - मात्र 1000 रुपये
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के अंतर्गत 30 सितंबर, 2015 को मिड-डे मील नियम, 2015 अधिसूचित किए। इसके अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को कितना भोजन दिया जायेगा? - 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाला

अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 20 अगस्त, 2014 को मंजूरी प्रदान की। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से मौजूदा वर्ष से लेकर किस वर्ष तक क्रियान्वित किया जायेगा? - वर्ष 2018 तक
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 7 नवंबर, 2014 को गोद लिया? - जयापुर गांव

दौलत) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार लगभग 20,050 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपये का निवेश समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपये का निवेश कृषिरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्रों में भी कई पहलों की शुरुआत की। इस योजना प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं-

- वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना।
- वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1,00,000 करोड़ रुपये तक करना।
- मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना।
- पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20-25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।

ई-गोपाला एप

10 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ-साथ ई-गोपाला एप भी लॉन्च किया, जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है। यह पोर्टल निम्नलिखित पहलुओं पर सम्बन्ध प्रदान करेगा-

- देश में पशुधन के सभी रूपों (वीर्य, ध्रुण, आदि) में रोगमुक्त जीवाणु (जर्मप्लाज्म) को खरीदना और बेचना।
- गुणवत्तापूर्ण प्रजनन संवाओं की उपलब्धता (कृत्रिम गर्भाधान, पशु प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार आदि) और पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करना।

- केंद्र सरकार ने घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए 18 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में किसान विकास पत्र योजना (केवीपी) की फिर से शुरुआत की। इस नए किसान विकास पत्र में धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जायेगी?
- 8 वर्ष और चार माह
- किसान विकास पत्र बचत योजना सबसे पहले किस वर्ष शुरू की गई थी?
- वर्ष 1988
- 25 दिसंबर, 2014 को देशभर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को किस अन्य दिवस के रूप में भी मनाया गया?
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिवस
- 25 दिसंबर, 2014 को संचार मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में ई-सेवा देने के लिए किस विशेष योजना का श्रृंगार किया?
- ज्ञान सेतु
- अर्द्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने 29 दिसंबर, 2014 को छोटे किसानों के लिए कौन-सा गैजट देने का शुभारंभ किया?
- ग्रीन फैबलेट
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में घरों में ऊर्जा की बचत करने वाले किस बिजली उपकरण के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम के तहत 5 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया?
- एलईडी बल्ब
- केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के उद्यमियों हेतु 16 जनवरी 2015 को 'अनुसूचित जाति उद्यम पूंजी कोष' नामक विशेष योजना प्रारंभ की। इस कोष की प्रारंभिक पूंजी कितनी है?
- 200 करोड़ रुपये
- केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और फिर से जीवित करने के प्रयास के मद्देनजर 21 जनवरी, 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया?
- राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्द्धन योजना (इवय)
- हृदय योजना के आरंभिक चरण में 12 विरासत शहरों को चुना गया है, जिन्हें फिर से जीवंत बनाया और विकसित किया जायेगा। केंद्र सरकार इन शहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया है?
- 500 करोड़ रुपये
- रेल बजट (2015-16) के तहत किसानों को नई जानकारी और खेती के नए तरीके जानने-समझने के लिए आने-जाने को आसान करने के लिए किस योजना की प्रारंभ की जायेगी?
- किसान यात्रा योजना
- केंद्र सरकार ने 25 अगस्त, 2015 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर किस टेलीमेडिसिन योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत लोग वीडियो लिंक द्वारा डॉक्टर से बात कर सकेंगे तथा जेनेरिक दवाएं भी ले सकेंगे?
- सेहत योजना
- केंद्र सरकार ने खनन से सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव हेतु 17 सितंबर, 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया?
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 16 सितंबर, 2015 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट शहरों की तर्ज पर ही स्मार्ट गांव विकसित करने, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन के तहत कितनी राशि मंजूर की गई?
- 5142 करोड़ रुपये

- उचित आयुर्वेदिक दवा/एथनो पशु चिकित्सा दवा का उपयोग करते हुए जानवरों का उपचार आदि की जानकारी देना।
- पशु किसानों को अलर्ट भोजना (टीकाकरण, गर्भावस्था निदान आदि के लिए नियत तारीख पर)।
- किसानों को क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में सूचित करना।

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2020 पर अपने भाषण के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के शुभारंभ का घोषणा की। इस मिशन के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जायेंगे। यह मिशन प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश भर में स्वास्थ्य सेवा में परेशानी मुक्त पहुँच के लिए एक अनूठा स्वास्थ्य खाता रखने में सक्षम करेगा। इस एकमात्र स्वास्थ्य पहचान पत्र में प्रत्येक जाँच, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टरों द्वारा दी गयी दवाइयाँ, रिपोर्ट और संबंधित सूचनाएँ रहेंगी। यह एक पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित पहल होगी और इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है। इस मिशन को नीति आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एक जगह पर रखा जायेगा। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगा जिसमें व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। एनडीएचएम के 6 प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं- 1. हेल्थ आईडी, 2. डिजिटल डॉक्टर, 3. स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, 4. व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, 5. ई-फार्मसी, 6. टेलीमेडिसिन।

सामाजिक क्षेत्र, निर्धनता एवं बेरोजगारी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर, 2015 को **स्वर्ण मौद्रीकरण योजना** (गोल्ड मोनेटाइजेशन) का शुभारंभ किया। इसके तहत सार्वभौम गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार की ओर से बॉन्ड की पहली सीरीज के लिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत कितनी निर्धारित की है? - **2,684 रुपये प्रति ग्राम**
- 5 दिसंबर, 2015 को केंद्र सरकार की 'उज्ज्वल डिस्कॉम आवासन योजना' (उदय) में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना? - **आन्ध्र प्रदेश**
(दूसरा- झारखण्ड एवं तीसरा- राजस्थान)
- यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने 5 जनवरी, 2016 को किस योजना का शुभारंभ किया? - **गंगा ग्राम योजना**
- गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रारंभ की गई गंगा ग्राम योजना के तहत किस गांव को गंगा ग्राम घोषित किया गया है? - **पूठ गांव**
- शिपिंग मंत्रालय ने 19 जनवरी, 2016 को किस परियोजना का शुभारंभ किया, जिससे देश भर में फैले प्रमुख बंदरगाह और ज्यादा स्वच्छ एवं हरियाली युक्त हो जाएंगे? - **परियोजना हरित बंदरगाह**
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत कितने रूबन क्लस्टरों को विकसित करने की घोषणा की गई है? - **300 रूबन क्लस्टरों**
- दिल्ली की सड़कों पर विकने वाले स्ट्रीट फूड के सुरक्षामानकों में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवारकल्याण मंत्री ने 14 मार्च, 2016 को किस अभियान का शुभारंभ किया? - **क्लीन स्ट्रीट फूड अभियान**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च, 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य कब तक सभी के लिए आवास मुहैया कराना है? - **वर्ष 2022 तक**
- नीति आयोग ने 27 अप्रैल, 2016 को राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता सृजन के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? - **शहरी प्रबंधन कार्यक्रम (UMP: Urban Management Program)**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से ग्रामीण महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की? - **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में 8000 करोड़ रुपये से तीन वर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पहले वर्ष में 1.5 करोड़ कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार इस योजना के तहत प्रति मुफ्त कनेक्शन पर कितनी सब्सिडी देगी? - **1600 रुपये**
- 2009 में यूपीए सरकार ने गांव के लोगों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना प्रारंभ की थी। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2014 में गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की योजना शुरू की। भारत में रसोई गैस (एलपीजी) देने का काम किस वर्ष से चल रहा है? - **वर्ष 1955 से**
- भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम 'उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिए रियायती एलईडी' (उजाला) का शुभारंभ 30 अप्रैल, 2016 को किस शहर में किया गया? - **भोपाल**

आत्मनिर्भर भारत योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना (Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan- ANBA) की घोषणा की, जिससे देश के 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो सकें। वस्तुतः प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस पैकेज को ही आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। यह पैकेज देश की जौड़ीपी का 10 प्रतिशत है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा के प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को तथा द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ इस प्रकार हैं-

- अर्थव्यवस्था (Economy), जो वृद्धिशील परिवर्तन (Incremental Change) के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो।
- अवसंरचना (Infrastructure), ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
- प्रौद्योगिकी (Technology), 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली।
- गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography), जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
- मांग (Demand), भारत की मांग और आपूर्ति मूल्यता की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।